सं. ए-45011/3/2022-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 22,मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को जनवरी, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, जेएस एंड एफए (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    वरिष्ठ सलाहकार (सीएण्डसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी और आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ सलाहकार (आईईआर) सीएएए।
18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम और सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल - 2022

ए-45011/3/2022-प्रशासन.III

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः जनवरी, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

I. इस माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. वृहदआर्थिक अवलोकन:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम और पहला संशोधित अनुमान बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 6.6% की कमी के बाद 2021-22 में 9.2% की वास्तविक जीडीपी विस्तार देखने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य यह है कि समग्र आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी के स्तर से आगे निकल गई है।

सरकारी खर्च से महत्वपूर्ण योगदान के साथ 2021-22 में कुल खपत में 7.0% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसी तरह, अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण सकल स्थायी पूंजी निर्माण महामारी पूर्व स्तर से अधिक हो गया। 2021-22 में अब तक वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा है, लेकिन घरेलू मांग में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में सुधार के साथ आयात में भी मजबूती आई है।

महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष 3.3% बढ़ने के बाद 2021-22 में इस क्षेत्र के 3.9% बढ़ने की उम्मीद है। पहले अग्रिम अनुमान और पहले संशोधित अनुमान बताते हैं कि उद्योग के जीवीए (खनन और निर्माण सहित) में 2020-21 में 3.3% के अनुबंध के बाद 2021-22 में 11.8% की

वृद्धि होगी। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल है। पिछले साल के 7.8 फीसदी के संकुचन के बाद इस वित्त वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है।

प्रमुख बहु-पक्षीय और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि भारत 2021 (वित्त वर्ष 21-22) में 8%-10% के बीच वृद्धि करेगा और ऐसा ही सरकार भी करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.0-8.5% की जीडीपी वृद्धि देखी जा सकती है। आईएमएफ ने 2021-22 और 2022-23 दोनों में भारत की वास्तविक जीडीपी 9% और 2023-24 में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह भारत को तीनों वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करता है। श्रम ब्यूरो ने अर्थव्यवस्था के नौ प्रमुख क्षेत्रों (अर्थात विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियां) के लिए 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में दूसरे तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के आंकड़े जारी किए हैं। क्यूईएस के दूसरे दौर (जुलाई-सितंबर, 2021) से नौ चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 3.10 करोड़ निकला, जो क्यूईएस (अप्रैल-जून, 2021) के पहले चक्र से अनुमानित रोजगार (3.08 करोड़) से 2 लाख (0.65%) अधिक है। । क्षेत्रवार विकास दर **अनुबंध** में दी गई है।

2. **महत्वपूर्ण घटनाक्रम:**

(i) अनुपूरक अनुदान मांग का दूसरा बैच संसद में पारित किया गया है।

(ii) भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत निम्नलिखित ऋण सहायता (एलओसी) विस्तारित और समर्थित की गई:

(क) रक्षा परियोजनाओं के लिए मेडागास्कर सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी; तथा
(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए श्रीलंका सरकार को 500 मिलियन अमरीकी डालर का अल्पकालिक एलओसी।

(iii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) केएफडब्ल्यू के साथ सूरत मेट्रो परियोजना के लिए 2 मिलियन यूरो का अनुदान;

(ख) केएफडब्ल्यू के साथ स्थायी भूमि प्रबंधन मेघालय के लिए 4.49 मिलियन यूरो का अनुदान;

(ग) विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल बिजली वितरण ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 135 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;